भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4351
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>बिहार में सौर ऊर्जा योजनाएं</u>

4351. श्री गोपाल जी ठाकुरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के दरभंगा जिले में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई और कार्यान्वित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से कितना लाभ प्राप्त हुआ है, उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): सरकार ने बिहार के दरभंगा जिले सहित देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

(घ) सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ङ) दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में ~102.57 गीगावाट की समग्र क्षमता के साथ सौर परियोजनाएं स्थापित की गई है। यह परियोजनाएं बिजली उत्पादन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्थानीय रोजगार, कार्बन उत्सर्जनों में कमी आदि सहित विभिन्न लाभ प्रदान करती है।

अनुलग्नक-**I**

'बिहार में सौर ऊर्जा योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4351 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

अनुलग्नक-II

'बिहार में सौर ऊर्जा योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4351 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पिछले तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि

(करोड़ में)

वित्त वर्ष	संशोधित अनुमान चरण में आवंटित धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
2021-22	3499.87	2732.86
2022-23	4980.46	3881.27
2023-24	6041.56	4834.07

*****